Dainik Jagran
Rebadi sanskriti par viraam lage:
May 25, 2023 | Chandigarh | Pg No.: 1,6 | Top Left | Rahul Verma | Sq Cm: 1853 |
AVE: 2935576 | PR Value: 14677880

संपादकीय

रेवड़ी संस्कृति पर विराम लगे:

एक राजनीतिक दल को मुफ्त

उपहारों से जुड़ी अपनी योजना तो कल्याणकारी लगती है, पर दूसरे दल की योजना रेवड़ी दिखती है। यह दृष्टिकोण बदलना होगा। राहुल वर्मा का सुझाव।

Dainik Jagran
Rebadi sanskriti par viraam lage:
India Media Monitor
May 25, 2023 | Chandigarh | Pg No.: 1,6 | Top Center | Rahul Verma | Sq Cm: 1853 | AVE: 2935576 | PR Value: 14677880

रेवड़ी संस्कृति पर विराम लगे

राहुल वर्मा

राजनीतिक दल को मुफ्त उपहारों ड़ी अपनी योजना तो कल्याणकारी ी है, पर दूसरे दल की योजना रेवड़ी ती है। यह दृष्टिकोण बदलना होगा

र्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही चुनाव में किए गए पांच वादों को क स्वीकृति प्रदान की है। इन पांच हर गृहिणी को 2,000 रुपये प्रति ा और घर को 200 यूनिट बिजली ी जानी है। गरीब परिवारों को हर 10 किलो चावल और महिलाओं श्शुल्क बस यात्रा की सुविधा वहीं, डिप्लोमाधारक बेरोजगारों माह 1,500 और डिग्रीधारकों को रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया एक मोटे अनुमान के अनुसार य वादों की पूर्ति के चलते राज्य के खजाने पर हर साल करीब करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्त 22-23 के लिए कर्नाटक के बजट 564 करोड़ रुपये के राजकोषीय अनुमान लगाया गया जो राज्य ल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 6 प्रतिशत के बराबर है। ऐसे में करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय से राज्य के खजाने पर बढ़ने वाले भारी बोझ का सहज ही आकलन किया जा सकता है। बहरहाल, कांग्रेस को कर्नाटक में मिली चुनावी सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने इस तरह की लोकलुभावन पेशकश शुरू कर दी हैं। इससे पहले दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसे सफलता का राजनीतिक सूत्र बना लिया। वहीं, अब कर्नाटक की कामयाबी से उत्साहित होकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा में इस तरह की योजनाओं का एलान किया है। हरियाणा में तो कांग्रेस ने 100 गज के प्लाट तक देने का एलान किया है। आखिर जमीन जैसे दुर्लभ संसाधन को लेकर कोई पार्टी किस प्रकार ऐसा वादा कर सकती है। खासतौर से शहरी इलाकों में।

ऐसे में आगामी आम चुनाव से पहले इस प्रकार की घोषणाओं की बाढ़ आ सकती है। यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए शुभ संकेत नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व में भी कई राज्यों को अनावश्यक खर्चों के लिए चेता चुका है। ऐसे में क्या यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि चुनावी घोषणापत्रों को व्यावहारिक बनाने की दिशा में मंथन शुरू किया जाए। चूंकि रेवड़ियां बांटने में कोई भी दल किसी से पीछे नहीं है तो इसमें कोई सर्वमान्य हल आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखता। इस मामले में चुनाव आयोग भी दलों के लिए कोई बाध्यकारी प्रविधान नहीं बना सकता। वहीं उच्चतम न्यायालय ने भी 2013 में कह दिया कि वह इसमें कोई व्यवस्था नहीं बना सकता और उसने गेंद राजनीतिक दलों के पाले में डाल दी, लेकिन दलों के स्तर पर इस विषय में कोई गंभीरता नहीं दिखती। कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना

अवधेश राजपूत

के जिन्न को बोतल से बाहर निकालना इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी आलोचना कांग्रेस की ओर झुकाव रखने वाले बुद्धिजीवी भी कर चुके हैं।

क्या मुफ्त उपहारों की पेशकश ही चुनावों में निर्णायक सिद्ध होकर किसी दल को सत्ता दिलाने में सहायक होती है। कर्नाटक के हालिया उदाहरण को ही देखें तो वहां केवल कांग्रेस ने ही नहीं, बल्कि भाजपा और जनता दल-सेक्युलर ने भी कमोबेश इसी प्रकार के वादे किए थे। स्पष्ट है कि चुनाव में केवल यही घोषणाएं ही मायने नहीं रखतीं। इस सिलसिले में 2015 में हमने दिल्ली में एक शोध किया था। शोध में शामिल एक समूह ने माना कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उन्हें मुफ्त में मिलेंगी तो अच्छा है। वहीं जब उन्हें यह बताया गया कि इन सुविधाओं से सरकारी खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा तो मुफ्त सुविधाओं को पसंद करने वालों की संख्या में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आ गई। स्पष्ट है कि यदि जनता में इसे लेकर जागरूकता का प्रसार होगा तो संभव है कि राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। भले ही इस मामले में चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय ने अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी हो, लेकिन कहीं न कहीं जनता, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों सहित समूचे तंत्र से जुड़े अंशभागियों को इस मुद्दे का कोई कारगर हल निकालना होगा। जनता को राजनीतिक दलों से यह प्रश्न करना चाहिए कि इन वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे, क्योंकि इसमें केवल वर्तमान की राजनीति का ही नहीं, बल्कि भविष्य के आर्थिक संतुलन का भी सवाल है। तब शायद दलों को इन वादों के साथ ही उन्हें पूरा करने की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करनी पड़े और फिर जनता उसी आधार पर निर्णय करे।

फिलहाल लोकलुभावनवाद को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है, जिसमें सभी दल बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, परंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र से मदद की गुहार लगाने से भी गुरेज नहीं करते। जैसे पंजाब की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से 50,000 करोड़ रुपये क सीमित संसाधनों और वि को देखते हुए केंद्र सरका प्रस्तावों से इन्कार स्वाभा ऐसी प्रतिक्रिया को लेकर में आक्रोश है, क्योंकि कि जीएसटी के बाद क उनके पास अधिकार नहीं में उनके योगदान के अनु साझेदारी में हिस्सेदारी न मामले में दक्षिण के राज्यों कि कर संग्रह में उनका होने के बावजूद संसाधन प्रदेश और बिहार जैसे र होता है। संसाधनों की सा तमिलनाडु के पूर्व वित्त म रूप से अपना पक्ष भी रख

स्पष्ट है कि यदि रेव विराम लगाना है तो राज अपना सुविधावादी दृष्टि होगा। एक राजनीतिक उपहारों से जुड़ी अप कल्याणकारी लगती है, दल की योजना रेवड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेवड़ी संस्कृति से मुक्ति हैं, लेकिन ऐसी पेशकशों उनकी पार्टी भाजपा भी नि:संदेह, रेवड़ी संस्कृ लगाना समय की मांग है लिए सभी को जिम्मेदारी संवेदनशीलता का परिच अन्यथा भारत को विकि का जो स्वप्न हम देखते है कठिन होता जाएगा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी
response@